जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 124 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 7 मार्च, 2026 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

## 'मैं कांग्रेस का राज्यसभा का उम्मीदवार हूँ, कल पर्चा भर रहा हूँ, आप आ जाएं'

### करमवीर बौद ने यह फोन भूपेन्द्र हूडा, सुरजेवाला, शैलजा आदि को किया, सभी नेता स्तब्ध रह गये

- राहुल गांधी, करमवीर बौद, एक अपरिचित से पूर्व बसपा नेता का चयन कर, बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें अपना एक दलित मिल गया, जो उनके दलित एजेंडे पर ''फिट'' बैठता है।
- बौद हरियाणा कांग्रेस के हल्कों में एक अपरिचित प्राणी हैं, जो कभी भी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई या, अन्य किसी संगठनात्मक पद पर नहीं रहे, और हाल ही में कांग्रेस से जुड़े हैं।
- वे एक सरकारी कर्मचारी थे, तथा भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित थे तथा फिर नौकरी से रिटायर होकर बसपा से जुड़े। तदोपरान्त कांग्रेस पार्टी में आए, पूर्व आईएएस अधिकारी के. राजू के संरक्षण में।
- हरदम की तरह राहुल गांधी ने दलित मामले के. राजू को सौंप रखे हैं तथा के. राजू ही दलित मामलों में पार्टी के सभी निर्णय लेते हैं। के. राजू की तगड़ी सिफारिश से करमवीर बौद को कांग्रेस का टिकिट मिला, क्या राहुल, जयजगत और के.सी. वेणुगोपाल के बारे में बिहार के अपने अनुभव के बाद कुछ नहीं सीखे कि, एक दलित पूर्व आईएएस अफसर के. राजू को दलित मामलों में सर्वेसर्वा बना दिया है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। कांग्रेस राज्यसभा टिकट देने के लिए कैसे प्रत्याशी चुनती है, यह उसकी संपूर्ण गाथा है।

जादू से टोपी से खरगोश निकालने की तरह कांग्रेस ने आखिरी समय में हरियाणा का अपना एकमात्र राज्यसभा टिकट एक अनजान व्यक्ति को दे दिया, जिसका नाम करमवीर बौद है, जो एक दलित हैं और कांग्रेस में उन्हें कोई नहीं जानता। उनके पास कोई संगठनात्मक अनुभव नहीं है, न ही उनका युवा कांग्रेस, एनएसयूआई या किसी अन्य पद से कोई संबंध है और वे हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं।

हरियाणा के कांग्रेसी एक-दूसरे को संदेश भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वे आखिर कैसे दिखते हैं!!

दिलचस्प बात यह है कि वे हरियाणा सरकार के कर्मचारी थे, जो दलित संगठन से जुड़े हुए थे और कभी-कभी सरकार और संगठन के बीच बड़े विवादों में मध्यस्थ का काम करते थे। उन्हें बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में चार साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। वे सेवानिवृत्त हुए और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## कोटा का डॉक्टर बना यूपीएससी टॉपर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। राजस्थान के लिए गर्व का पल। कोटा के अनिल अग्निहोत्री, जो पेशे से डॉक्टर हैं, ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन (सीएसई) 2025 में टॉप रैंक हासिल की है। यह उपलब्धि उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में हासिल की।

अनुज अग्निहोत्री ने इस परीक्षा में टॉप किया, जबकि राजेश्वरी सुवे एम और आकाश धुल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अनुज ने मेडिकल साइंस को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था।

- डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने तीसरे प्रयास में यह शानदार सफलता प्राप्त की है। उन्होंने मैडिकल साइन्स को बतौर विषय चुना था।

अपनी इस अद्वितीय उपलब्धि के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए, 26 वर्षीय अनुज ने कहा, ''मैं अपनी सफलता का मुख्य कारण भाग्य को मानता हूं।''

अनुज की टॉप करने की यात्रा आसान नहीं थी। यह उनका तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में उन्हें दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## क्या ट्रम्प ईरान युद्ध के तनाव से टूट से रहे हैं?

### वे वाइट हाऊस में अपनी ''ऑफिशियल'' कुर्सी में सम्मोहित से बैठे नज़र आए, अपनी पूजा में आंख बंद किए अपने प्रभु से मदद मांगते हुए

- यह सच है कि, जिस ''आराम'' से वे वेनेज़ुएला पर विजय पा सके थे, उसकी तुलना में ईरान के आक्रामक जवाब ने उन्हें हिला दिया है। ट्रंप के आसपास विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरु, उनके सिर पर, कंधे पर हाथ लगाकर हिम्मत बढ़ाते नज़र आये। वे ऐसे हारे हुए व्यक्ति लग रहे थे मानो उन्हें दूसरी दुनिया से मदद की जरुरत महसूस हो रही थी।
- वैसे भी ट्रंप अब विरोधाभासी दावे कर रहे हैं, जिनका तथ्यों से कोई सरोकार नहीं लगता।
- एक तरफ तो वे, ईरानी दूतावासों के अधिकारियों से कह रहे हैं, कि वे अपनी जिम्मेवारी छोड़कर बाहर आ जायें, और अन्य देशों की सरकारों से संरक्षण की मांग करें। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ का ट्रैफिक खुलवाने की कोशिश में, व्यवसायिक जहाजों को अमेरिकी नौ सेना की सुरक्षा में स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ पार करवाने का वादा करते हैं।

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 6 मार्च। सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान युद्ध के दबाव में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कोई हैरानी नहीं कि ईरान ने, उनके वैनेज़ुएला अनुभव की तुलना में, जिस तरह जबरदस्त जवाबी हमला किया है और ईरान युद्ध में मदद देने को लेकर उनके नाटो सहयोगियों के बीच साफ मतभेद भी सामने आ गए हैं, ऐसी स्थिति में ट्रंप को अपने मौजूदा संकट से निकलने के लिए हर तरह की भौतिक, आध्यात्मिक और यहां तक कि अलौकिक मदद की जरूरत महसूस हो रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास, द वाइट हाउस, आज असाधारण दृश्यों का गवाह बना। एक बूढ़े व्यक्ति की तरह ट्रंप आत्माओं की दुनिया से तुरंत मदद की प्रार्थना करते हुए एकदम स्तब्ध बैठे थे।

यह एक अजीब सा नाटक जैसा दृश्य था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को धार्मिक नेताओं द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा था, वह भी ओवल ऑफिस जैसे स्थान पर। ट्रंप अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे और उनके चारों ओर कई धार्मिक नेता खड़े होकर गंभीर स्वर में शांति, सबके लिए न्याय और इसी तरह की बातें कर रहे थे।

इन धार्मिक नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति को छूते हुए देखा गया, कुछ उनके हाथ पकड़ रहे थे, तो कुछ उनके कंधों पर हाथ रखे हुए थे। ट्रंप आंखें बंद किए, परेशान चेहरे के साथ अपनी कुर्सी पर असहज तरीके से बैठे दिखाई दे रहे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बिहार में एक अनजाने चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा

### चर्चा है कि संघ पृष्ठभूमि वाली सीमा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है

- इस कदम से भाजपा को कई लाभ होने की संभावना है, एक तो वह बिहार में नई शुरुआत का संकेत देना चाहती है। दूसरे पार्टी को उम्मीद है कि इससे पड़ौसी राज्य प.बंगाल, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, में भारी फायदा होगा।
- नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के असंभव कार्य में सफल होने के बाद भी भाजपा कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा पर उपमुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के पुत्र से पेशकश की गई है।
- सूत्रों ने कहा, भाजपा जद (यू) में विभाजन की कोशिश भी नहीं करेगी क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति भारी सहानुभूति है लोगों, खासकर महिलाओं में, इसलिए भाजपा कोई दुस्साहस नहीं करेगी और नीतीश के प्रति भारी सद्भावना दिखाएगी।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। ऐसी संभावनाएँ हैं कि भाजपा नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार के स्थान पर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसी कम पहचान वाली महिला नेता को नियुक्त कर सकता है, जैसा कि भजनलाल शर्मा के मामले में किया था।

अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, जैसे इज़राइल-ईरान युद्ध और एप्स्टीन फाइल्स में भाजपा और केन्द्र सरकार व्यस्तता के बीच, अंततः नीतीश कुमार को दरवाजा दिखा देने का निर्णय एक आश्चर्यचकित करने वाला कदम साबित हुआ है। लेकिन दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पहला, भाजपा शॉक ट्रीटमेंट देने की अपनी क्षमता पर फलती-फूलती आ रही है। दूसरा, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होना पार्टी के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के चुनावों में मददगार साबित होगा। इससे भी ज्यादा फायदा उस स्थिति में होगा, अगर भाजपा नेतृत्व इस काम के लिए किसी कम पहचान वाली महिला नेता का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## उमेश सिंह कुशवाहा जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने

पटना, 06 मार्च। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह कुशवाहा को लगातार तीसरी बार पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। शुक्रवार को पटना स्थित जदयू के प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक चुनाव की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया।

- वे लगातार तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार 'मुन्ना' और परमहंस कुमार ने उन्हें अध्यक्ष पद का प्रमाण-पत्र सौंपा। इससे पहले उमेश सिंह कुशवाहा ने चार सैट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तय समय-सीमा तक इस पद के लिए उनके अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया। इसके बाद स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें निर्विरोध बिहार प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया।

## 'अमेरिका ने दया की, भारत को रुस से कच्चा तेल लेने की अनुमति दी'

### अमेरिका के ट्रैज़री सैक्रेटरी ने कहा कि भारत को यह काम चलाऊ छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए दी गई है।

- स्कॉट बेसैंट ने कहा कि भारत इस अवधि में रुस से वही तेल खरीद पाएगा जो पहले से समुद्र में विचरण कर रहे टैंकरों में जमा है और इससे रुस को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इससे ईरान युद्ध से बढ़े दबाव से भारत को कुछ राहत मिलेगी। तथापि, भारत को इसके लिए मौजूदा रेट पर ही कीमत अदा करनी होगी।
- इस अनुमति के साथ ही भारत ने तेल मंगाने की प्रक्रिया शुरु कर दी। दो टैंकर भारत की ओर निकल चुके हैं इनमें से हरेक में 7 लाख बैरल तेल है, चर्चा है कि तीसरा टैंकर भी भारत की ओर बढ़ रहा है।
- इस समय रुस का 9.5 लाख मिलियन बैरल कच्चा तेल समुद्री टैंकरों में जमा है और भारत के आसपास ही मंडरा रहा है।
- भारत सरकार ने भारतीय तेल कंपनियों को रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 06 मार्च। दया भाव दर्शाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत को ''अस्थायी'' रूप से रूस से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे दी है, और इस पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लिया जाएगा और भारतीय सरकार ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करते हुए रिफाइनरियों को रसोई गैस की कमी से बचने के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया, क्योंकि मध्य पूर्व युद्ध के कारण एलपीजी की भारी कमी हो सकती थी।

कतर से, जो भारत का प्रमुख एलपीजी आपूर्तिकर्ता है, चिंताजनक रिपोर्ट मिलने के बाद मोदी सरकार ने अमेरिकी राहत का तुरंत उपयोग किया, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में आने वाले संकट को टाला जा सके।

''द फाइनेंशियल टाइम्स'' से एक साक्षात्कार में, कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने कहा कि युद्ध के कारण खाड़ी देशों में ऊर्जा उत्पादन बंद हो सकता है, तेल की कीमत 150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है और ''दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नीचे ला सकता है''।

कतर, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिक्विड नैचुरल गैस (एलएनजी) उत्पादक है, इस सप्ताह अपने रास लाफन संयंत्र पर एक ईरानी ड्रोन हमले के बाद उत्पादन रोकने पर मजबूर हो गया, जो कि इसका सबसे बड़ा एल पी जी संयंत्र है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर छूट की कांग्रेस ने निंदा की

नई दिल्ली, 06 मार्च । अमेरिका के वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट देने संबंधी बयान की कांग्रेस ने निंदा की है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका-इजरायल के दबाव में काम कर रहे हैं और सरकार की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रही। भारत को अमेरिका से अनुमति मिल गई है कि वह 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सके।

- पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका-इज़रायल के दबाव में काम कर रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## अमेरिका के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है नाटो देशों में

### नाटो के सदस्य देश अमेरिका से अलग, स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने के संकेत दे रहे हैं

- स्पेन द्वारा अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना इसी की शुरुआत माना जा रहा है।
- स्पेन का कहना है कि नाटो का सदस्य होने का मतलब अमेरिका के हरेक सैन्य अभियान में अनिवार्य रुप से भागीदारी करना नहीं है।
- स्पेन व अन्य देशों में अमेरिका के प्रति बढ़ते असंतोष की एक बड़ी वजह उन देशों की आंतरिक राजनीति भी है। स्पेन में जनभावना दूसरे देशों, खासकर मिडिल ईस्ट, में सैन्य हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ है। स्पेन का मत है कि युद्ध लंबा खिंचा तो, मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा और इससे यूरोप पर शरणार्थियों का भार पड़ेगा।
- स्पेन का यह रुख इराक वॉर की कटु स्मृतियों के कारण है। वर्ष 2003 में स्पेन की तत्कालीन सरकार ने इराक में अमेरिकन घुसपैठ का समर्थन किया था, इस पर स्पेन में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। मैड्रिड में ट्रेन धमाके हुए, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। बाद में जब वहां समाजवादी सरकार बनी तो उसने इराक से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ देने से स्पेन के इनकार ने हाल के वर्षों में पश्चिमी गठबंधन के भीतर सबसे गंभीर मतभेदों में से एक को उजागर कर दिया है। हालांकि स्पेन नार्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन (नाटो) का सदस्य है, लेकिन प्रधानमंत्री पैडो सांचेज़ की सरकार ने साफ कर दिया है कि मैड्रिड न तो इस सैन्य अभियान में भाग लेगा और न ही स्पेन की जमीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने देगा। इस रुख ने स्पेन को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ सीधे टकराव में ला दिया है और इससे ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन की एकता पर भी बड़े सवाल उठे हैं।

विवाद की तात्कालिक वजह यह है कि स्पेन ने अमेरिका को अपने संयुक्त सैन्य ठिकानों, नेवल स्टेशन रोटा और मोरोन में अपने जॉइंट मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ युद्ध से जुड़ी कार्रवाई के लिए करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इन ठिकानों पर, लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत, अमेरिकी सेना मौजूद रहती है और ये भूमध्यसागर तथा मध्य-पूर्व में अमेरिकी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केन्द्र रहे हैं। मैड्रिड ने जोर देकर कहा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ऐसे आक्रामक सैन्य अभियानों के लिए नहीं किया जा सकता, जिनके लिए अंतरराष्ट्रीय कानून या संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत कोई साफ मैनडेट न हो। इस तरह रेखा खींचकर सांचेज़ सरकार ने वॉशिंगटन को स्पेन की जमीन को इस संघर्ष के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल करने से रोक दिया।

यह विवाद जल्दी ही मैड्रिड और वॉशिंगटन के बीच एक डिप्लोमैटिक टकराव में बदल गया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्पेन की आलोचना करते हुए कहा कि उसने गठबंधन की एकजुटता का साथ नहीं दिया और यहां तक कि ट्रेड में बदले की कार्रवाई का संकेत भी दिया। हालांकि स्पेन अपने फैसले पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी

नई दिल्ली, 06 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा, सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई। उनकी समर्पण भावना, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में उन अभ्यर्थियों का भी हौसला

- उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को उनकी समर्पण भावना, दृढ़ता व कड़ी मेहनत ने इस उपलब्धि तक पहुंचाया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)